औद्योगिक विकास की नई कहानी गढ़ रहा यूपी

यूपी में 2017 में डबल इंजन की सरकार आने के बाद से प्रदेश में जिस प्रकार से कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उससे व्यापारियों का भरोसा लौटा है। औद्योगिक नीतियों को व्यवसाय की सुगमता के अनुकूल बनाया गया है। योगी सरकार में यहां की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। शायद यही वजह है कि आम जनता हो या बड़े उद्योगपति, सभी का विश्वास योगी सरकार पर बढ़ा है।

सचिन अग्रवाल,
सीएमडी, पीटीसी इंडस्ट्रीज

बीते दिनों लखनऊ में आयोजित तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देश-विदेश के शीर्ष उद्योगपतियों, केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों की उपस्थिति में 80,324 करोड़ की 1406 औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास व भूमिपूजन हुआ। यह समारोह फरवरी 2018 में हुए पहले इन्वेस्टर्स समिट की श्रृंखला में तीसरा मौका था कि जब हम सभी योगी सरकार के वादों व दावों को जमीन पर उतरते हुए देख रहे थे। पहले समिट में प्रदेश को करीब 4.68 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसमें से विगत पांच वर्षों में तीन लाख करोड़ के प्रस्ताव क्रियान्वित हो चुके हैं। योगी सरकार में मैन्यूफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे पारंपरिक बिजनेस की मांग को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में काफी बेहतर काम हुआ है।

पावर ग्रिड हो, गैस पाइपलाइन का नेटवर्क हो या फिर मल्टी माडल कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में काम हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर-बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को पंख लगाने का काम करेंगे। लखनऊ-कानपुर, वाराणसी-कोलकाता और गोरखपुर-सिलिगुड़ी एक्सप्रेसवे प्रदेश की दशा-दिशा बदलने वाले हैं। सभी एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्र को औद्योगिक विकास के नजरिए से विकसित किया जाएगा। गलियारों में खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई इकाइयां वेयरहाउस और लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना पर काम हो रहा है। कुशीनगर के बाद अब अयोध्या और जेवर सहित पांच अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट यहां की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। बेहतर कनेक्टिविटी और बढ़ता हुआ निवेश प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े अवसर लेकर आने वाले हैं।

यूपी में 2017 में औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति लागू हुई थी। इसके साथ ही प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्रैंडली 20 सेक्टोरल पॉलिसीज को उद्यमिता, इनोवेशन और मेक इन इंडिया की तर्ज पर आगे बढ़ाने का काम किया गया। श्रम, भूमि आवंटन, संपत्ति रजिस्ट्रेशन, पर्यावरणीय अनुमोदन सहित 500 से अधिक सुधार किए गए है। सिंगल विंडो सिस्टम से निवेश को और सुगम बनाया गया है। नीतियों को निवेश फ्रैंडली बनाने, कानून-व्यवस्था बेहतर करने व ओडीओपी जैसे प्रयासों से विगत पांच वर्ष में 1.61 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिले हैं।